भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4354 का उत्तर

नासिक-दहानू रेललाइन और त्र्यंबकेश्वर तक रेल संपर्क

4354. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नासिक-दहानू रेललाइन की दीर्घकाल से लंबित मांग पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय रेल योजना या अमृत भारत स्टेशन योजना जैसी योजनाओं के तहत तकनीकी व्यवहार्यता, भूमि अधिग्रहण तथा वित्तीय आयोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2027 के कुंभ मेले, जब करोड़ों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, के मद्देनजर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए सीधा रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए नासिक से त्र्यंबकेश्वर तक रेल ट्रैक के निर्माण और प्रचालन को प्राथमिकता देगी; और

(घ) यदि हां, तो कुंभ मेला 2027 से पहले इस महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा, बजट आवंटन और योजनाबद्ध कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): नाशिक-त्र्यंबकेश्वर-वाणगांव-दहानू रोड (100 कि.मी.) तक नई लाइन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) की स्वीकृति दी गई है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना (एनएमपी) के अंतर्गत एकीकृत योजना, वर्धित लॉजिस्टिक क्षमता और जनता, माल और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए कमियों को दूर करने, पर्यटक और सांस्कृतिक स्थानों सहित औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, बिजली संयंत्रों, कृषि क्षेत्रों के लिए संपर्कता के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए मौजूदा रेल नेटवर्क के नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किए जाते हैं।

भारतीय रेल पर रेल परियोजनाओं को मंजूरी देना सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेलवे की अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्ग, भीड़भाड़/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत और 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

कार्य की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	16	2,017	166	8,529
आमान परिवर्तन	2	609	312	3,332
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	23	3,251	1,448	19,376
कुल	41	5,877	1,926	31,236

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और अन्य कार्यों हेतु औसत बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,171 करोड़ रूपए प्रति वर्ष
2025-26	23,778 करोड़ रूपए (20 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाले रेलखंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रतिवर्ष (3 गुना अधिक)

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन का सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोर के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, औरंगाबाद, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चंदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (डीडीआर), दादर (डीआर), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हज़ूर साहिब नांदेड़, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, इगतपुरी, इतवारी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोल्हापुर, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी, कुर्ला, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद, लोनावाला, लोअर परेल,

		मलाड, मलकापुर, मनमाड, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज, मुदखेड़, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़, नासिक रोड, उस्मानाबाद, पाचोरा, पालघर, पंढरपुर, पनवेल, परभणी, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव, पुणे जं., पूर्णा, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार

महाराष्ट्र राज्य के नासिक संसदीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। इनमें से कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- देवलाली स्टेशन पर प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वारमण्डप, चारदीवारी, नया प्लेटफार्म शेल्टर, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, लिफ्टों का प्रावधान, मानक साइनेज, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
- मनमाड स्टेशन पर नए प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार का कार्य पूरा किया गया है तथा प्रवेश द्वार, स्टेशन भवन, शौचालय, बुकिंग कार्यालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, संकेतकों, स्टेशन प्रकाश व्यवस्था, नए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण, लिफ्ट और एस्कलेटर का प्रावधान आदि के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।
- लासलगांव स्टेशन पर स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर के प्रावधान का सुधार कार्य, प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, शौचालय और नए बुकिंग कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

- **इगतपुरी स्टेशन पर नए प्रवेश द्वार, ऊपरी पैदल पुल की सीढ़ियों के लिए कवर शेड, नए शौचालय ब्लॉक और अपशिष्ट उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और नए बुकिंग कार्यालय, सेवा भवन, स्टेशन भवन के सुधार आदि के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।**
- **कोपरगांव स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म की सतह, सायबान शेड के निर्माण, नए ओवरहेड जल टैंक, भूमिगत सम्प और अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर के प्रावधान के सुधार कार्य पूरे किए जा चुके हैं और नए शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र आदि के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।**

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नासिक रोड स्टेशन के विकास के लिए मास्टर योजना बनाई जा रही है। यह एक आवर्ती प्रक्रिया है जिसमें इष्टतमीकरण की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर ऐसे इष्टतमीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। महाराष्ट्र राज्य चार जोनों अर्थात मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 3,854 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों से संबंधित कार्यों की स्वीकृति भारतीय रेल की सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की आवाजाही और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर शुरु किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, नासिक जिले में निम्नलिखित ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं:-

नासिक जिले में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य	
मदें	ऊपरी/निचले सड़क पुलों के चल रहे कार्य
ऊपरी सड़क पुल	16
निचले सड़क पुल	4
कुल	20

किसी भी ऊपरी/निचले सड़क पुलों से संबंधित कार्यों का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि समपार बंद करने हेतु सहमति के लिए राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण को हटाना, बाधक जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित

करना, विभिन्न अधिकारियों से सांविधिक मंजूरियाँ, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशिष्ट परियोजना/कार्य स्थलों के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अतः ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों के समापन के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करना काफी कठिन है।

****